का एक नया डिजाइन विकसित किया है जिसमें स्टील के गैस होल्डर नहीं होते है । इस नए डिजाइन से लागत कम हो गई है और इसे उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय बनाया जा रहा है ।

राजस्थान में ग्रामीण उद्योगों का विकास

1951. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास राजस्थान में ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : (क) और (ख). राजस्थान में समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के ग्रामीण उद्योग, सेवा तथा व्यापार घटक के अन्तर्गत प्रत्येक खण्ड में प्रतिवर्ष 100 परिवारों को लाया जाना है । इस कार्यक्रम में उद्यमियों द्वारा लघु, कुटीर तथा घरेलू औद्योगिक यूनिटों की स्थापना का प्रावधान है और उद्यमी/कारीगर को इस प्रयोजन हेतु 3000 रूपए तक का उपदान दिया जाता है । विशेषकर इस कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए खण्डों में उद्योग विस्तार अधिकारियो की तैनाती की गई है । खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग और राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा भी खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्रम के अन्तर्गत लाये गये 25 ग्रामोद्योगों में यूनिटों की स्थापना करने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता तथा विपणन सहायता सुलभ की जानी है । ऊन परिष्करण, ग्रामीण चमड़ा तथा ग्रामीण कुम्हारी की यूनिटों पर विशेष बल दिया गया है । दरी विनिर्माण यूनिटों की स्थापना की जा रही है तथा इन कार्यों में लगे हुए कारीगरों की कुशलताओं में सुधार किया जा रहा है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के लिए वैज्ञानिक का चयन

1952. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन कृषि अनुसंधान बोर्ड जो केवल एक व्यक्ति वाली एक समिति है, द्वारा प्रत्याशियों का चयन अनुचित है ; और

(ख) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन की प्रक्रिया अपनाई जायेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन): (क) विज्ञानिकों की भर्ती कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल के माध्यम से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सोसायटी के नियमों तथा उप-नियमों के अनुसार की जाती है तथा उस रूप में यह अनुचित नहीं है । चयनों की चयन समितियों द्वारा अन्तिम रूप दिया जाता है जिनमें कि संबधित शाखाओं में दो या तीन विशेषज्ञ होते हैं तथा कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मंडल के अध्यक्ष या उसके द्वारा नामित व्यक्ति के अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक प्रतिनिधि होता है । रू० 2000 से 2500 तथा उससे ऊपर के ग्रेड पदों को भर्ती के लिए चयन समितियों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष (कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री) द्वारा दो सलाहकार नामजद किये जाते है ।

(ख) उम्मीदवारों के चयन के लिए कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल द्वारा लगभग वही प्रक्रियाएं अपनायी जाती हैं जोकि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अपनायी जाती हैं ।

राज्यों में मद्य-निषेध

1953. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :**
श्री मूल चन्द डागा :

क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या है जिन में मद्य निषेध लागू किया गया था और बाद में समाप्त कर दिया गया है ;

(ख) क्या सरकार पूरे राष्ट्र में मद्य निषेध की नीति पर विश्वास करती है ; और

(ग) जिन राज्यों में मद्य निषेध लागू किया गया था उन में मद्य पान करने वाले व्यक्तियों की सख्या में कमी क्यों नहीं हो पाई है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और बिहार सरकारों ने संबंधित राज्यों में पूर्ण मद्यनिषेध लागू किया था । बिहार सरकार ने अलबत्ता राज्य में पूर्ण मद्यनिषेध हटा दिया है ।

(ख) भारत सरकार संविधान में दी गई नीति के प्रति वचनबद्ध है ।

(ग) इस पर कोई टिप्पणी देना सम्भव नहीं है क्योंकि शराब के व्यवसनी व्यक्तियों की संख्या के बारे में कोई व्यापक सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

Apex Body for Housing Development Schemes

1954. SHRI P. M. SAYEED: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether the Centre has asked the States to set up an apex body of development authorities for better coordination in respect of housing development schemes;

(b) if so, whether many of the States have started implementing the suggestions;

(c) whether Union Territories were also asked to do the same;

(d) whether the Ministry feel that there was a shortage of two crore housing units in the country and three-fourth being in the rural areas;

(e) if so, the steps which are being taken in this regard; and

(f) whether both Centre and State Governments have agreed to build these and cover them during the Sixth Five Year Plan?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

(d) Yes, Sir. According to the estimate made by NBO, Housing shortage in the country in April 1980 was of the order of 20.7 million units, 4.6 million units in urban areas and 16.1 million units in rural areas.

(c) and (f). Housing is a state subject. Central Financial assistance is given in the States for the State Sector Programmes, including Housing, in the form of 'Block loans' and 'Block grants' without being tied to any particular scheme or head of development. As the housing problem